



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 मई, 2018 ई0 (बैशाख 29, 1940 शक सम्वत्) [संख्या-20

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	247-252	1500
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	407-427	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	123-127	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

समाज कल्याण अनुभाग-04

अधिसूचना

02 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 49/XVII-4/2018-01(04)/वि0क0/2017-T.C.-दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 84 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के प्रयोजन के लिए मा0 मुख्य न्यायाधीश, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से राज्य के प्रत्येक जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ० रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

27 मार्च, 2018 ई0

संख्या 511/II (1)-2018-01(73)/2017-नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री त्रिभुवन सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13क, ₹ 1,31,100-2,16,600 में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री त्रिभुवन सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
3. इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

27 मार्च, 2018 ई0

संख्या 511(i)/II (1)-2018-01(73)/2017-नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री जयपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13क, ₹ 1,31,100-2,16,600 में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री जयपाल सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। श्री जयपाल सिंह द्वारा पदोन्नति के पद पर कार्यभार उक्त पद के वास्तविक रूप से रिक्त होने पर ही ग्रहण किया जायेगा।

3. इनकी पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

27 मार्च, 2018 ई0

संख्या 513/II (1)-2018-01(42)(430)/2012-नियमित चयनोपरान्त श्री राकेश कुमार तिवारी, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13, ₹ 1,23,100-2,15,900 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री तिवारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।

4. उक्त पदोन्नति ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 22/एस०बी०/2016, श्री सुभाष चन्द्र बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग-3

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2018 ई०

संख्या 1425/XX-3-2018-05(17)2013-श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस सम्बन्ध में श्रीमती शदाब बागो, सप्तम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-252/XX-3-2017-05(17)2013, दिनांक 19.04.2017 को विखण्डित करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संख्या-49, वर्ष 1988) की धारा-3(1) एवं 4(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में विचारण हेतु श्रीमती सुजाता सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके दायित्वों के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी (सी०बी०आई०), उत्तराखण्ड के रूप में पदाभिहित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2018 ई०

संख्या 1426/XX-3-2017-05(17)2013-श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस सम्बन्ध में श्री अजय चौधरी, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-322/XX-3-2017-05(17)2013, दिनांक 17.05.2017 को विखण्डित करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संख्या-49, वर्ष 1988) की धारा-3 के अधीन मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गढ़वाल परिक्षेत्र से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अधिष्ठान, अपराध अनुसंधान विभाग एवं पुलिस अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्री राजीव कुमार खुल्बे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2018 ई०

संख्या 1427/XX-3-2018-05(17)2013-श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस सम्बन्ध में सुश्री कुमकुम रानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल से सम्बन्धित

अधिसूचना संख्या-905/XX-3-2016-05(17)2013, दिनांक 24.11.2017 को विखण्डित करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संख्या-49, वर्ष 1988) की धारा-3 के अधीन मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल की संस्तुति पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुमाऊँ परिक्षेत्र से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अधिष्ठान, अपराध अनुसंधान विभाग एवं पुलिस अवस्थापना द्वारा पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्री सी0 पी0 बिजलवान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अधिसूचना

26 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 1428/XX-3-2018-05(01)2016-श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 02, वर्ष 1974) की धारा 11 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस सम्बन्ध में सुश्री आफिया मतीन, न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, देहरादून से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 1220/XX-3-2016-05(01)2016, दिनांक 13.07.2016 को विखण्डित करते हुए, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के परामर्श से साइबर क्राइम पुलिस थाना, देहरादून में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2000) के अन्तर्गत पंजीकृत वादों के विचारण हेतु श्री सचिन कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, देहरादून को पदाभिहित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

13 मार्च, 2018 ई0

संख्या 114/XVIII (3)/2018-3(3)/2017-श्री राज्यपाल महोदय, संयुक्त प्रान्त भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम 'टिहरी भागीरथी नगर' के अन्तर्गत कुल 385 हेक्टेअर भूमि, सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रहेंगी।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	गाँव/मोहल्ले का नाम	कुल भूमि
1	2	3	4	5
हरिद्वार	हरिद्वार	ज्वालापुर	टिहरी भागीरथी नगर	385 हेक्टेअर

आज्ञा से,
हरबंस सिंह चुध,
प्रमारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 114/XVIII(3)/2018-3(3)/2017, dated March 13, 2018 for general information.

NOTIFICATION

March 13, 2018

No. 114/XVIII(3)/2018-3(3)/2017—In exercise of the powers conferred by section 48 of the United Provinces Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the total 385 Hectare land of village 'Tehri Bhagirathi Nagar' mentioned in the Schedule below shall be under Survey and Record Operations with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette :—

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village/Mohalla	Total Land
1	2	3	4	5
Hardwar	Hardwar	Jwalapur	Tehri Bhagirathi Nagar	385 Hectare

By Order,

HARBANS SINGH CHUGH,
Secretary In-charge.

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 357/XXXI(4)/18/04(विविध)/2016—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री त्रिलोक चन्द्र तिवारी, प्रमुख निजी सचिव को नियमित वयनोपरान्त वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान ₹ 1,23,100—2,15,900, पे-मैट्रिक्स लेवल-13, (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37,400—67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री त्रिलोक चन्द्र तिवारी को वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के पद पर 06 माह की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०), अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4. संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण में मा० सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा० सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय एवं मा० उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका (S.L.P.) संख्या 10600—10601/2011, श्री कृष्ण कुमार मदान व अन्य बनाम अशोक कुमार व अन्य तथा मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 239/2016(एस०/बी०), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ०प्र० सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तदक्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित/परमार्जित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 358/XXXI(4)/18/04(विविध)/2016—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र भट्ट, मुख्य निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त अपर सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान ₹ 1,31,100—2,16,600 पे—मैट्रिक्स लेवल—13क, (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37,400—67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दिनेश चन्द्र भट्ट को अपर सचिव के पद पर 06 माह की विहित परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तदक्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 359/XXXI(4)/18/04(विविध)/2016—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री दर्शन सिंह, वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त मुख्य निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान ₹ 1,31,100—2,16,600, पे—मैट्रिक्स लेवल—13क, (अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37,400—67,000, ग्रेड पे ₹ 8,900) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दर्शन सिंह को मुख्य निजी सचिव के पद पर 06 माह की विहित परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0), अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

4. संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति श्री लाल सिंह नागरकोटी, निजी सचिव (तदर्थ) के प्रकरण में मा0 सक्षम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तदक्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,
हरबंस सिंह चुघ,
सचिव (प्रभारी)।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 मई, 2018 ई0 (बैशाख 29, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 05, 2018

No. 71/UHC/XIV-a/33/Admin.A/2013--Ms. Nazish Kaleem, Civil Judge (Jr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 04.09.2017 to 02.03.2018 with permission to prefix 02.09.2017 and 03.09.2017 as holidays in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009, dated 24.08.2009 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

April 05, 2018

No. 72/UHC/XIV-a/42/Admin.A/2012--Sri Avinash Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 19.03.2018 to 28.03.2018 with permission to prefix 18.03.2018 as Sunday holiday and suffix 29.03.2018 as Mahavir Jayanti holiday.

NOTIFICATION

April 05, 2018

No. 73/UHC/XIV-a/55/Admin.A/2012--Ms. Indu Sharma, Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 12.03.2018 to 28.03.2018 with permission to prefix 10.03.2018 & 11.03.2018 as 2nd Saturday and Sunday holidays and suffix 29.03.2018 as Mahavir Jayanti holiday.

NOTIFICATION

April 05, 2018

No. 74/UHC/XIV/95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, the then Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar, presently posted as Chief Judicial Magistrate, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 12.02.2018 to 25.02.2018 with permission to prefix 10.02.2018 & 11.02.2018 as 2nd Saturday & Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

April 07, 2018

No. 75/UHC/XIV-a/42/Admin.A/2013--Sri Vinod Kumar, 5th Additional District Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 21.02.2018 to 28.02.2018.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 139/UHC/Admin.A/2018--Sri Arvind Nath Tripathi, Additional Judge, Family Court, Rishikesh, District Dehradun is repatriated and posted as Chief Judicial Magistrate, Nainital.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Nainital, in addition to his duties.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 140/UHC/Admin.A/2018--Sri Rakesh Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Bageshwar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Chamoli, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 141/UHC/Admin.A/2018--Sri Rajoo Kumar Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 142/UHC/Admin.A/2018--Sri Kuldeep Sharma, Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag, vice Sri Sudhir Tomar.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 143/UHC/Admin.A/2018--Ms. Meena Deopa, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Hardwar is repatriated and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 144/UHC/Admin.A/2018--Sri Vivek Srivastava, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun is repatriated and posted as 1st Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, vice Smt. Savita Chamoli.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 145/UHC/Admin.A/2018--Sri Sudhir Tomar, Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh, *vice* Sri Kuldeep Sharma.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh, in addition to his duties.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 146/UHC/Admin.A/2018--Sri Mukesh Chandra Arya, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital is also given additional charge of Additional Chief Judicial Magistrate (Railways), Haldwani, District Nainital, in addition to his present duties.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 147/UHC/Admin.A/2018--Smt. Sangeeta Rani, Additional Chief Judicial Magistrate (Railways), Haldwani, District Nainital is posted as Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, District Nainital, *vice* Sri Sundeep Kumar.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 148/UHC/Admin.A/2018--Sri Laxman Singh, Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar is transferred and posted as Chief Judicial Magistrate, Bageshwar, *vice* Sri Rakesh Kumar Singh.

He is also given additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Bageshwar, in addition to his duties.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 149/UHC/Admin.A/2018--Sri Dharendra Bhatt, Additional Chief Judicial Magistrate, Hardwar is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Udham Singh Nagar, *vice* Sri Laxman Singh.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 150/UHC/Admin.A/2018--Sri Sundeep Kumar, Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, District Nainital is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Tehri Garhwal, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 151/UHC/Admin.A/2018--Sri Bhavdeep Ravtey, Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwar, District Pauri Garhwal is transferred and posted as Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Dehradun, *vice* Sri Mohd. Yusuf.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 152/UHC/Admin.A/2018--Ms. Akata Mishra, Civil Judge (Sr. Div.), Pithoragarh, is transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Hardwar, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 153/UHC/Admin.A/2018--Sri Rajeev Dhavan, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is repatriated and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Karanprayag, District Chamoli, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 154/UHC/Admin.A/2018--Ms. Chhavi Bansal, Civil Judge (Jr. Div.), Ramnagar, District Nainital is promoted, transferred and posted as Joint Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, in the vacant Post.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 155/UHC/Admin.A/2018--Ms. Ritika Semwal, Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Hardwar is promoted and posted as 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, *vice* Smt. Jyoti Bala.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 156/UHC/Admin.A/2018--Ms. Vibha Yadav, Assistant Director, Uttarakhand Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is promoted in the cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 157/UHC/Admin.A/2018--Sri Sanjay Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag is promoted and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 158/UHC/Admin.A/2018--Sri Sayed Gufran, Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District Pauri Garhwal is promoted, transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, in the vacant Court.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 159/UHC/Admin.A/2018--Ms. Indu Sharma, Judicial Magistrate, Rishikesh, District Dehradun is promoted, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Kotdwara, District Pauri Garhwal, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, *vice* Sri Bhavdeep Ravtey.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 160/UHC/Admin.A/2018--Sri Manoj Kumar Dwivedi, Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Hardwar is promoted in the cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 161/UHC/Admin.A/2018--Smt. Niharika Mittal Gupta, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar is promoted in the cadre of Civil Judge (Sr. Div.) in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 162/UHC/Admin.A/2018--Sri Harsh Yadav, Civil Judge (Jr. Div.), Chamoli is promoted, transferred and posted as Civil Judge (Sr. Div.), Khatima, District Udham Singh Nagar, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, vice Sri Rajoo Kumar Srivastava.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 163/UHC/Admin.A/2018--Sri Ravi Shanker Mishra, Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar is promoted, transferred and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Hardwar, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, vice Sri Dharendra Bhatt.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 164/UHC/Admin.A/2018--Sri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is promoted and posted as Additional Chief Judicial Magistrate, Roorkee, District Hardwar, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, vice Ms. Shivani Pasbola.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 165/UHC/Admin.A/2018--Ms. Seema Dungarakoti, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is promoted and posted as 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun, in the pay scale of ₹ 39,530-920-40,450-1,080-49,090-1,230-54,010, vice Sri Mohd. Yaqoob.

This order will come into force w.e.f. 16.04.2018.

Note 1--The officers transferred prematurely on their request will not be allowed the transfer travelling allowance.

Note 2--Recommendations have been sent to the State Legal Services Authority, Uttarakhand, Nainital for the posting of following officers as Secretary, District Legal Services Authorities:--

- (i) Sri Abdul Qayyum--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Dehradun.
- (ii) Sri Nandan Singh--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Tehri Garhwal.
- (iii) Sri Laxman Singh (now transferred as C.J.M., Bageshwar)--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Bageshwar, in addition to his duties.
- (iv) Ms. Shivani Pasbola--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Hardwar.

- (v) Sri Mohd. Yaqoob--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Champawat.
- (vi) Sri Sanjay Singh (now promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.))--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Rudraprayag, in addition to his duties.
- (vii) Sri Manoj Kumar Dwivedi (now promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.))--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A. Pithoragarh.
- (viii) Smt. Niharika Mittal Gupta (now promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.))--Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Nainital.

Note 3--Recommendations have been sent to the State Government for the posting of following officers on deputation posts mentioned against their names :

1. Smt. Savita Chamoli [1st Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun]--As Additional Judge, Family Court, Dehradun, in the vacant Court.
2. Sri Mohd. Yusuf [Pr. Magistrate/J.M. (1st Class, J.J.B., Dehradun)]--As O.S.D., State Legal Services Authority, Nainital, in the vacant post.
3. Smt. Jyotsna [Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, D.L.S.A., Bageshwar]--As Additional Judge, Family Court, Rishikesh, District Dehradun, vice Sri Arvind Nath Tripathi.
4. Smt. Jyoti Bala [2nd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar]--As Additional Judge, Family Court, Roorkee, District Hardwar, in the vacant Court.
5. Ms. Vibha Yadav [Asstt. Director, UJALA, Bhowali, Distt. Nainital]--As Joint Registrar (Judicial & Admin.), Public Service Tribunal, Uttarakhand, Dehradun, in the vacant Post.

Above transfers will come into effect after the receipt of respective notifications from the State Legal Services Authority & State Government.

By Order of the Court,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 166/UHC/XIV-62/Admin.A/2004--Sri Amit Kumar Sirohi, Additional District & Sessions Judge, Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 22.03.2018 to 31.03.2018 with permission to suffix 01.04.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 21, 2018

No. 172/UHC/XIV-90/Admin.A--Sri Mithilesh Jha, Chief Judicial Magistrate, Uttarkashi is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 19.03.2018 to 26.03.2018.

NOTIFICATION

April 21, 2018

No. 173/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2012--Smt. Niharika Mittal Gupta, the then Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District Udham Singh Nagar, presently posted as Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned medical leave for 28 days w.e.f. 04.03.2018 to 31.03.2018.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

April 24, 2018

No. 174/UHC/Admin.B--In the exercise of powers conferred under section 19(1) of the Right to information Act, 2005 (Act 22/2005), the High Court of Uttarakhand do hereby designate Registrar (Inspection), High Court of Uttarakhand as the Appellate Authority for the High Court of Uttarakhand vice Registrar (Judicial), High Court of Uttarakhand with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

NOTIFICATION

April
May 01, 2018

No. 176/UHC/XIV-a/32/Admin.A/2015--Ms. Meenal Chawla, the then Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora, presently posted as 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned medical leave for 71 days w.e.f. 04.02.2018 to 15.04.2018.

NOTIFICATION

May 01, 2018

No. 177/UHC/XIV/39/Admin.A--Sri G. K. Sharma, District & Sessions Judge, Almora is hereby sanctioned medical leave for 12 days w.e.f. 07.03.2018 to 18.03.2018.

NOTIFICATION

May 04, 2018

No. 178/UHC/XIV/54/Admin.A--Sri Prem Singh Khimal, District & Sessions Judge, Champawat is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 10.04.2018 to 21.04.2018 with permission to suffix 22.04.2018 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

April 05, 2018

No. 431/III(4)-B-2009-10/SLSA--Sri Bharat Bhushan Pandey, Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for a period of 05 days w.e.f. 05.03.2018 to 09.03.2018 alongwith prefix 04.03.2018 as Sunday holiday and suffix 10.03.2018 as 2nd Saturday holiday and 11.03.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

April 05, 2018

No. 432/III(4)-B-2009-10/SLSA--Sri Bharat Bhushan Pandey, Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for a period of 11 days w.e.f. 14.03.2018 to 24.03.2018 alongwith suffix 25.03.2018 as Sunday holiday.

By order of Hon'ble Executive Chairman,
Sd/-

PRASHANT JOSHI,
Member Secretary.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 456/I-H-1/SLSA/2018--In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 (subsequent Amendment Rules, 2016) and pursuant to the recommendation of the Hon'ble High Court of Uttarakhand, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital hereby appoints the following Judicial Officers as Chairman in the Permanent Lok Adalats in the district mentioned against their name:--

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 454/III-4-B/SLSA/2018--Sri Pankaj Tomar, 1st Additional District Judge, Udham Singh Nagar is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Udham Singh Nagar vice Sri Bharat Bhushan Pandey.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 455/III-3-B/SLSA/2018--Sri Brijendra Singh, F.T.C/Addl. District Judge/Special Judge, POCSO, Udham Singh Nagar is appointed as Chairman, Permanent Lok Adalat, Nainital vice Sri Om Kumar.

NOTE : This order will come into force w.e.f. 16.04.2018.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 465/I-H-1/SLSA/2018--In view of the powers conferred under Section-9(3) of the Legal Services Authorities Act, 1987, Rule-12(1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2015 and pursuant to the recommendation of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as Secretary, District Legal Services Authority in the district mentioned against their name :--

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 457/III-A-5/SLSA/2018--Sri Abdul Qayyum, Civil Judge (Sr. Div.)/Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Dehradun vice Sri Vivek Srivastava.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 458/III-A-11/SLSA/2018--Sri Nandan Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Tehri Garhwal *vice* Sri Abdul Qayyum.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 459/III-A-6/SLSA/2018--Ms. Shivani Pasbola, A.C.J.M., Roorkee, District Hardwar is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Hardwar *vice* Ms. Meena Deopa.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 460/III-A-4/SLSA/2018--Sri Mohd. Yaqoob, 3rd Addl. Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Champawat.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 461/III-A-9/SLSA/2018--Sri Manoj Kumar Dwivedi, Judicial Magistrate-I, Roorkee, District Hardwar {promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.)} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 462/III-A-7/SLSA/2018--Smt. Niharika Mittal Gupta, Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur, District U. S. Nagar {promoted to the cadre of Civil Judge (Sr. Div.)} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Nainital *vice* Sri Rajeev Dhavan.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 463/III-A-9/SLSA/2018--Sri Laxman Singh, {now transferred as C. J. M., Bageshwar} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar, in addition to his present duties.

NOTIFICATION

April 12, 2018

No. 464/III-A-9/SLSA/2018--Sri Sanjay Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Rudraprayag {promoted as Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag} is appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Rudraprayag, in addition to his present duties.

NOTE : This order will come into force w.e.f. 16.04.2018.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRASHANT JOSHI,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

April 18, 2018

(Taking over on transfer)

No. 1645/UHC/Admin.A/2018—CERTIFIED That the office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over in the forenoon of April 18, 2018 in compliance of Notification No. 89/UHC/Admin.A/2018, dated April 11, 2018 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

Smt. SHADAB BANO.

Countersigned,

NARENDRA DUTT,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

April 18, 2018

(Taking over on transfer)

No. 1646/UHC/Admin.A/2018—CERTIFIED That the office of the Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over in the forenoon of April 18, 2018 in compliance of Notification No. 80/UHC/Admin.A/2018, dated April 11, 2018 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

AJAY CHAUDHARY.

Countersigned,

NARENDRA DUTT,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand,

Nainital.

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

10 अप्रैल, 2018 ई०

पत्रांक 203/1-02-2017—प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 05.03.2018 से दिनांक 14.03.2018 तक (दिनांक 04.03.2018, रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए) अर्जित अवकाश का उपभोग किए जाने हेतु मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को आवेदन किया गया था एवम् पुनः दिनांक 15.03.2018 से दिनांक 07.04.2018 तक (दिनांक 08.04.2018, रविवार अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) अर्जित अवकाश हेतु मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को

आवेदन किया जा रहा है। दिनांक 05.03.2018 से दिनांक 14.03.2018 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत होने एवम् दिनांक 15.03.2018 से दिनांक 07.04.2018 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत होने की प्रत्याशा में, मेरे द्वारा अर्जित अवकाश का उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 09.04.2018 की पूर्वाह्न में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कुलदीप शर्मा,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट),
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग

कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र

19 अप्रैल, 2018 ई0

पत्रांक 344(vii)/एक-04-2018-प्रमाणित किया जाता है कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना संख्या 142/यू0एच0सी0/एडमिन.ए/2018, अप्रैल 12, 2018 के अनुपालन में, मेरे द्वारा आज दिनांक 19.04.2018 को पूर्वाह्न में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रप्रयाग का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

कुलदीप शर्मा,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट),
जनपद न्यायाधीश,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

06 अप्रैल, 2018 ई0

पत्रांक 187/एक-03-2016-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के पत्र संख्या 1196/XIV-a/52/Admin.A/2012, दिनांक मार्च 21, 2018 के द्वारा दिनांक 22.03.2018 से दिनांक 05.04.2018 तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप उक्त पितृत्व अवकाश का उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 06.04.2018 के पूर्वाह्न में सिविल जज (जू0डि0), पिथौरागढ़ का पदभार ग्रहण किया गया है।

अकरम अली,
सिविल जज (जू0 डि0),
पिथौरागढ़।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट),
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण-पत्र

02 अप्रैल, 2018 ई०

पत्रांक 01(viii) श्रम न्यायालय/कार्यभार/व्य०प०/ /2018-प्रमाणित किया जाता है कि मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की अधिसूचना सं० 62/UHC/Admin.A/2018, दिनांक 22.03.2018 के अनुपालन में मेरा स्थानान्तरण 'जिला जज, नैनीताल' के पद पर होने के फलस्वरूप मेरे द्वारा 'पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार आज दिनांक 02.04.2018 की अपरान्ह में छोड़ दिया गया है।

सी० पी० बिजलवान,
पीठासीन अधिकारी,
श्रम न्यायालय,
देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षर
ह० (अस्पष्ट),
महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

प्रभार प्रमाण-पत्र

04 अप्रैल, 2018 ई०

पृष्ठांकन संख्या 07(vii)/श्र० न्या०दे०दून/2018-प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 478(1)/VIII/18-70(श्रम)/2001-II, दिनांकित 23 मार्च, 2018 सहपठित उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग की अधिसूचना/शुद्धि पत्र संख्या 502(1)/VIII/18-70(श्रम)/2001-II, दिनांक 02.04.2018, जिसके अनुसार उक्त अधिसूचना में दिनांक 23.03.2017 के स्थान पर 23.03.2018 पढ़ा जाय एवं माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निर्गत आदेश संख्या 1289/XIII-F-I/Admin.A/2010, दिनांकित 28.03.2018 के अनुपालन में पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून का पदभार, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 04.04.2018 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह० (अस्पष्ट),
सचिव, श्रम
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

मोचक अधिकारी
सिकन्द कुमार त्यागी,
पीठासीन अधिकारी,
श्रम न्यायालय,
देहरादून।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि-अनुभाग)

23 अप्रैल, 2018 ई०

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य०), राज्य कर,

देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 352/रा०कर आयु० उत्तरा०/रा०क०मु०/विधि-अनुभाग/18-19/देहरादून-उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 351/2018/19(120)/XXVII(8)/2012, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 की वार्षिक विवरणी दिनांक 30.06.2018 तक बिना विलम्ब शुल्क जमा किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना एवं आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना एवं आदेश की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग-8

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2018 ई०

संख्या 351/2018/19(120)/XXVII(8)/2012-चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35 की उपधारा (6) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित वार्षिक विवरणी दिनांक 30.06.2018 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा की जा सकेगी। दिनांक 30.06.2018 के उपरान्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 351/2018/19(120)/XXVII(8)/2012, Dated April 19, 2018 for general information.

NOTIFICATION

April 19, 2018

No. 351/2018/19(120)/XXVII(8)/2012--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and Sub-section (6) of Section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in Rule 11 of the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005 the Governor is pleased to declare that the annual return related to the tax assessment year 2016-17 may be filed upto 30.06.2018 without any late fee. After 30.06.2018 late fee shall be payable as per provision of Act and Rules.

By Order,
AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिशनर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून विज्ञप्ति

05 अप्रैल, 2018 ई०

संख्या 60/रा०प०-3-चक०सं०/2017-जिलाधिकारी/जिला उप संचालक, चकबंदी, पौड़ी-गढ़वाल के पत्र संख्या 409/पे०का०, दिनांक 29.08.2017, पत्र संख्या 17/पे०का०, दिनांक 27.10.2017 एवं पत्र संख्या 161/पे०का०, दिनांक 27.10.2017 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 821/XVIII(III)/2017-04(26)/2017TC, दिनांक 16.11.2017, शासनादेश संख्या 766/XVIII(III)/2017-04(26)/2017, दिनांक 09.11.2017 एवं शासनादेश संख्या 825/XVIII(III)/2017-04(26)/2017, दिनांक 01.12.2017 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-4 की उपधारा (2) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 3741/सी०एच०आई०ई०-454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या 85/XVIII(3)/2018-04(26)/2017, 26.02.2018 के अनुपालन में, मैं, सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर, तहसील पौड़ी एवं तहसील सतपुली के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित गाँवों में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबंदी क्रियायें आरम्भ करने में, इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबंदी क्रियायें की जायेगी।

क्र० सं०	ग्राम का नाम	पट्टी	तहसील
1.	खैरासैण	मल्ला बदलपुर	सतपुली
2.	पंचूर	उदयपुर वल्ला-3	यमकेश्वर
3.	औणी	इडवालस्यू	पौड़ी

विज्ञप्ति

05 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 61/रा0प0-3-चक0सं0/2017-जिलाधिकारी/जिला उप संचालक, चकबंदी, पौड़ी-गढ़वाल के पत्र संख्या 409/पे0का0, दिनांक 29.08.2017, पत्र संख्या 17/पे0का0, दिनांक 27.10.2017 एवं पत्र संख्या 161/पे0का0, दिनांक 27.10.2017 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 821/XVIII(III)/2017-04(26)/2017TC, दिनांक 16.11.2017, शासनादेश संख्या 766/XVIII(III)/2017-04(26)/2017, दिनांक 09.11.2017 एवं शासनादेश संख्या 825/XVIII(III)/2017-04(26)/2017, दिनांक 01.12.2017 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा-4 की उपधारा (1) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या 3741/सी0एच0आई0ई0-454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके, शासनादेश संख्या 85/XVIII(3)/2018-04(26)2017, दिनांक 26.02.2018 के अनुपालन में, मैं, सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील यमकेश्वर, तहसील पौड़ी एवं तहसील सतपुली में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबंदी क्रियायें की जायेगी।

सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,

संचालक, चकबंदी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6151/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.08.2017 को वाहन संख्या UK07AE-7486, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Deepak Paniyuly S/o Sri D. Paniyuly की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100733193, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.11.2010 से 08.11.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6152/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 18.08.2017 को वाहन संख्या UK08CA-3751, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Gulfam S/o Sri Bhure Khan की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720120212881, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.06.2012 से 20.06.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 12.10.2015 से 11.10.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6153/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.08.2017 को वाहन संख्या UK07AA-6138, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile, RC के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri M. S. Negi S/o Sri J. S. Negi की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720140284603, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.01.2014 से 08.01.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6154/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 17.08.2017 को वाहन संख्या UK07AV-1559, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Raghvindra S/o Sri Ramakant की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720110187304, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 06.12.2011 से 07.12.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6155/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.08.2017 को वाहन संख्या UK07BW-6696, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kalam Singh S/o Sri D. Rawat की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720110184805, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 18.11.2011 से 17.11.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6156/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.08.2017 को वाहन संख्या UK07CA-5523, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Anwar Khan S/o Sri Ahmad Ali की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720070023345, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 01.10.2007 से 30.09.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 11.08.2017 से 01.08.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6157/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 25.08.2017 को वाहन संख्या UK07CA-5546, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri M. Singh S/o Sri Foza Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720110156310, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.04.2011 से 14.04.2016 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 29.06.2015 से 28.06.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6158/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.08.2017 को वाहन संख्या UK07BQ-8206, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manoj Bansal S/o R. S. Bansal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-072008004275, जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 08.05.2008 से 22.02.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6159/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.08.2017 को वाहन संख्या UK07X-3122, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manoj Singh S/o Sri Kayan Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1620160008148, जो कि Vikasnagar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.03.2016 से 16.03.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6160/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.08.2017 को वाहन संख्या UK07BA-9970, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Mohd. Yusuf S/o Sri Deen Mohd. की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0719980044421, जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.12.1998 से 20.12.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6161/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.08.2017 को वाहन संख्या UK18F-2035, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kundan Kumar S/o B. Mishra की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720170006992, जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.04.2017 से 04.05.2035 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6162/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.08.2017 को वाहन संख्या UA07F-8078, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manmohan Singh S/o Sri O. P. Panwar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720140297799, जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 28.04.2014 से 27.04.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6163/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.08.2007 को वाहन संख्या UK07TA-5230, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Surender Joshi S/o Sri R. P. Joshi की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0719990206023, जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 15.07.1999 से 01.06.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 17.05.2017 से 12.04.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6164/लाइसेंस/2017—यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.08.2017 को वाहन संख्या UK07AT-5396, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Unsafe drive के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sumit Barthwal S/o Sri M. N. Barthwal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100105169, जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 22.03.2010 से 21.03.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6165/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.08.2017 को वाहन संख्या UK07AV-6166, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri D. S. Dhapola S/o Sri H. S. Dhapola की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720132073684, जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 11.10.2013 से 10.10.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6166/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.08.2017 को वाहन संख्या UK07CB-2105, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kailash Chandra S/o Sri Chandra Mani की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720080060766, जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 29.11.2008 से 28.11.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 04.05.2016 से 27.04.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6167/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या UA07J-3348, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kamal Kumar S/o Sri Ram Kumar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1420100016352, जो कि Rishikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 26.08.2010 से 25.08.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 09.08.2015 से 08.08.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपटित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6169/लाइसेंस/2017-यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.07.2017 को वाहन संख्या HROJA-9033, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री पवन शर्मा S/o श्री किशन लाल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या HR-019970008221, जो कि अम्बाला कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 08.08.1997 से 12.04.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक से तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(एफ) सपटित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-21 के उपनियम-09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-19 की उपधारा-1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 मई, 2018 ई0 (बैशाख 29, 1940 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा, पौड़ी (गढ़वाल)

सार्वजनिक सूचना

20 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 1065/यू0चा0/गजट/2017-18-सीमान्तर्गत नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा-2, खण्ड (झ)-(घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के दैनिक राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित की गई थी, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर पालिका बोर्ड बैठक 09.03.2018 को पारित प्रस्ताव संख्या 04 के अनुसार अन्तिम सूचना गजट नोटिफिकेशन हेतु प्रकाशित की जाती है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि-2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

1. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2017 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
4. परिभाषाएँ :
 - (a) नगरीय ठोस अपशिष्ट के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप में नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

- (b) उपविधि से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है, नगरपालिका से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका से है।
- (c) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य, नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।
- (d) सफाई निरीक्षक से तात्पर्य, निकाय में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध होने की स्थिति में निकाय के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।
- (e) निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय-समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।
- (f) नियम से तात्पर्य, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0-648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम 2016 बनाये गये से है।
- (g) अधिनियम से तात्पर्य, उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड नगरपालिका अधिनियम से है।
- (h) जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से, जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों-पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।
- (i) जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste) से तात्पर्य, ऐसे कूड़ा-कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा, कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।
- (j) पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जो किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके, उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि।
- (k) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste) से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित, किसी अनुसंधान, क्रिया-कलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।
- (l) संग्रहण (Collection) से तात्पर्य, अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।
- (m) कचरा खाद बनाने (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से है, जिससे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।
- (n) ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste) से, सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।
- (o) व्ययन (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।
- (p) भूमिकरण (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है।
- (q) निक्षालितक (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।
- (r) नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority) में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्ध और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

- (s) स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) का तात्पर्य, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पालिका, क्षेत्र पालिका या ग्राम पालिका है।
 - (t) नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
 - (u) सुविधा के परिचालक (Operator of facility) से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।
 - (v) पुनःचक्रण (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
 - (w) पृथक्करण (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग-अलग करना अभिप्रेत है।
 - (x) भण्डारण (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को वर्गों से अलग-अलग करना अभिप्रेत है।
 - (y) परिवहन (Transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा-करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।
5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित से जुर्माना वसूला जायेगा।
 6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्टों प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।
 7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगरपालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय-समय पर संशोधित करी जा सकेंगी, के अनुसार उत्पादन व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।
 8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर, पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।
 9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।
 10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार-द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा परिचालक को देना होगा।
 11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन, जीव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों को उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला, व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।
13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।
14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्ज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादन के द्वारा अथवा नगरपालिका/ सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्ज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।
15. अनुसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5/-को पूर्णांक में की जायेगी।
16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्ज/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची-1 सेवा शुल्क (User charges) बोर्ड बैठक दिनांक 31.08.2017 द्वारा निर्धारित

क्र० सं०	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि (₹ में)
1	2	3
1.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0 कार्डधारक के अतिरिक्त ₹ 5,000.00 प्रतिमाह तक आय वाले घर)	₹ 10.00
2.	मध्यम आय वाले घर (₹ 5,000.00 से अधिक ₹ 10,000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	₹ 15.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	₹ 20.00
4.	सब्जी एवं विक्रेता	ठेली पर फेरी में ₹ 3.00 प्रतिदिन दुकान/फड़ पर ₹ 100.00 प्रतिमाह
5.	रेस्टोरेन्ट	छोटे ₹ 50.00, मध्यम ₹ 100.00 तथा बड़े ₹ 500.00 प्रतिमाह
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	20 बेड तक ₹ 100.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 200.00 एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 300.00 प्रतिमाह
7.	आश्रम/अखाड़ा	20 बेड तक ₹ 50.00 प्रतिमाह, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 100.00 प्रतिमाह एवं 41 से अधिक बेड तक ₹ 200.00 प्रतिमाह तथा भण्डारा/उत्सव आयोजन ₹ 500.00 प्रति
8.	धर्मशाला	₹ 01.00 प्रति कमरा प्रतिमाह
9.	बारातघर (चेरिटेबल) (नान-चेरिटेबल)	₹ 200.00 प्रति उत्सव, ₹ 500.00 प्रति उत्सव
10.	बैकरी	₹ 100.00 प्रतिमाह
11.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक ₹ 100.00, 51 कर्मचारियों से 100 तक ₹ 200.00, 101 से 300 तक ₹ 300.00 एवं उससे अधिक पर ₹ 500.00 प्रतिमाह
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100 बेड तक के लिए ₹ 1000.00 प्रतिमाह, उससे अधिक ₹ 10.00 प्रतिबेड अतिरिक्त
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक ₹ 500.00 उससे अधिक ₹ 1,000.00 प्रतिमाह

1	2	3
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडीकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक ₹ 250.00, 21 बेड से 40 बेड तक ₹ 500.00, 41 बेड से 100 बेड तक ₹ 1,000.00, उससे अधिक ₹ 1,500.00 प्रतिमाह
15.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक ₹ 75.00, पैथोलॉजी ₹ 200.00 प्रतिमाह
16.	दुकान/चाय की दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान ₹ 20.00, बाजार की दुकान ₹ 50.00, शोरूम ₹ 100.00, छोटे मॉल ₹ 500.00, बहुमंजिल मॉल ₹ 1,000.00 प्रतिमाह, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
17.	फैक्ट्री	छोटी ₹ 300.00, मध्यम ₹ 500.00, बड़ी ₹ 1,000.00 प्रतिमाह
18.	वर्कशॉप	छोटी ₹ 300.00, मध्यम ₹ 500.00, बड़ी ₹ 1,000.00 प्रतिमाह
19.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	₹ 5.00 प्रतिदिन
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हों	₹ 300.00, होटलों में विवाह ₹ 1,000.00 प्रति उत्सव
21.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धित अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक ₹ 100.00, 1.0 घन मी0 तक ₹ 200.00, 3.0 घन मी0 तक ₹ 500.00, 6.0 घन मी0 तक ₹ 1,000.00, इससे अधिक प्रति घन मी0 ₹ 100.00 अतिरिक्त
22.	कबाड़ी	छोटे ₹ 100.00, बड़े ₹ 300.00 प्रतिमाह

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय/तो अग्रेंतर किया जाय, तो अग्रेंतर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, दुगड्डा, पौड़ी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

हर्षवर्धन सिंह रावत,
अधिशासी अधिकारी,
न0पा0प0, दुगड्डा।

दीपक बडोला,
अध्यक्ष,
न0पा0प0, दुगड्डा।